implemented by the Government and their public sector undertakings. The Government promote construction of low-cost houses in the implementation of schemes for social housing and financing of housing activities by the Housing and Urban Development Corporation so that the houses constructed are within the means of the people for whom the schemes are intended. For construction in the general pool also, the Government are economising on cost of construction.

V.I.Ps having their own Houses in Delhi using Government Accommodation

1946. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that those V.I.Ps. who have their own houses in Delhi are using Government accommodation paying even market rent; and

(b) if so, the number of houses, flats and other accommodation occupied by the un-authorised persons?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Allottees of Government quarters, who have their own houses in Delhi, are eligible for retention of Government quarters on payment of market rent. The house-owning restriction are not, however, applicable to V.I.P's such as Ministers, M.Ps., Judges of the Supreme Court, and the Delhi High Court and Members of the Planning Commission.

(b) The house-owning officers, who retain Government accommodation on payment of market rent, are not considered as un-authorised occupants.

दिल्ली प्रशासन द्वारा निलंबित किए गए अध्यापक

1947. **श्री शिव नारायण सरसूनिया:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आपात स्थिति के दौरान दिल्ली प्रशासन ने कितने अध्यापकों को निलंबित किया ; और

(ख) क्या निलंबित अध्यापकों को कोई आरोप-पत्र दिया गया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) :(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 57 अध्यापकों को निलम्बित किया गया था।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में निम्न वर्ग के कर्मचारियों को सरकारी मकानों का आवंटन

1948. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 70 प्रतिशत से अधिक निम्न वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली एवं अन्य शहरों में अभी तक सरकारी क्वार्टर नहीं दिए गए हैं और न ही उन्हें निकट भविष्य में मिलने की आशा है ;

(ख) क्या यह सच है कि दो हजार रुपये अथवा उस से अधिक वेतन पाने वाले सभी अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर मिल गए हैं;